**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2106**
**उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2026**

**दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क**

2106. **श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पहुंच में हुई संवृद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पहुंच में हुई संवृद्धि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में हुई संवृद्धि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों, सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

देश में मोबाइल कनेक्टिविटी (2जी/3जी/4जी) वाले गांवों की संख्या मार्च, 2022 में 6,05,230 से बढ़कर जून, 2026 में 6,36,013 हो गई है। इसी प्रकार, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी (3जी/4जी) वाले गांवों की संख्या मार्च, 2022 में 6,00,384 से बढ़कर जून, 2026 में 6,33,160 हो गई है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मोबाइल कनेक्टिविटी (2जी/3जी/4जी) वाले गांवों की संख्या मार्च, 2022 में 36,608 से बढ़कर जून, 2026 में 44,280 हो गई है और मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी (3जी/4जी) वाले गांवों की संख्या मार्च, 2022 में 35,817 से बढ़कर जून, 2026 में 43,697 हो गई है।

देश के 17,611 सीमावर्ती गांवों में से, अप्रैल, 2026 तक, 17,094 गांव 4जी कनेक्टिविटी से कवर हैं।

इसके अलावा, सरकार द्वारा वित्तपोषित 4जी सेचुरेशन परियोजना और अन्य मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत, दिनांक 30.06.2026 तक, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में 24,812 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने भारतनेट के चरण-I और चरण-II के तहत सृजित मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करने और नई ग्राम पंचायतों के लिए इंक्रीमेंटल नेटवर्क सृजित करने, बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को मांग के आधार पर जोड़ने, प्रचालन और रखरखाव, 1.5 करोड़ फाइबर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदित किया है। जून, 2026 तक, भारतनेट के तहत सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश की 80,472 ग्राम पंचायतें कार्यशील हैं।

*****